



भारतीय वाचनपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

वा. 209]

नई दिल्ली, भारतीय, जून 5, 1990/ज्येष्ठ 15, 1912

No. 209]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 1990/JYĀISTHA 15, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के हण्ड में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

खात्री और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

प्रधिमूलना

नई दिल्ली, 1 जून, 1990

सा. का. नि. 543(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक व्यूरो नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक व्यूरो (द्वारा संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक व्यूरो नियम, 1987 में, नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

“17क. ऐसा व्यय जिसकी बाबत बजट में उपबंध नहीं किया गया है—ऐसा व्यय जो ग्राकस्मिक और

आवश्यक प्रकृति का हो, किन्तु जिसकी बाबत बजट में कोई उपबंध न किया गया हो, केवल तब ही उपगत किया जाएगा जब कार्यकारी समिति ने उसका अनुमोदन कर दिया हो।

17क. विनियोग :—मंजूर किए गए बजट में उपबंधित नियमों की बाबत यह समझा जाएगा कि महानियोगकालीन विदेशक को बजट में प्राधिकृत और उपबंधित कियाकलापों और प्रयोजनों के लिए विभिन्न लेखा शीर्षी के अधीन व्यय को पूरा करने के लिए उसमें से किसी भी राशि का अपने प्रसादानुसार विनियोग करने के लिए पूर्ण शक्तियां होंगी :

परन्तु इन नियमों का विनियोग और पुनर्विनियोग ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा जिसकी मंजूरी ऐसे प्राधिकारी द्वारा न दी गई हो जो ऐसी मंजूरी देने के लिए सक्षम हो।

1/ग पुनर्विनियोग.—ग्राहांगेश्वर की ऐसे कियाकलापों और प्रयोजनों की परिधि के अन्तर्गत, जिनकी बाबत बजट में उपबंध किया गया है, ऐसी गणियों को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोग करने की अनियंत्रित प्राप्त होगी :

परन्तु ऐसे निधियों का पुनर्विनियोग निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा—

- (i) काम की किसी ऐसी नई मद पर व्यय को पूरा करने के लिए, जो बजट में अनुधृत नहीं है;
- (ii) किसी ऐसी परियोजना में संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए, जिसमें ऐसा निर्माण अन्तर्वलित हो जिसकी बाबत मध्यम प्राधिकारियों से प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी प्राप्त न की गई हो;
- (iii) किसी ऐसी परियोजना के रावंध में व्यय जो पूरा करने के लिए, जिसमें निर्माण प्रत्यंवलित हो, जो अनुमोदित प्राक्कलनों के दस प्रतिशत में ग्राधिक हो;
- (iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए बजट में व्यय की किसी विनिर्दिष्ट नई मद के लिए किए गए उपबंध से;
- (v) ऐसी निधियों से जिनकी बाबत उपबंध योजनागत शीर्ष के अधीन किया गया है व्यय की गैरयोजनागत शीर्ष में और पूजी से राजस्व में तथा विपर्येन, और
- (vi) “विदेशी यात्रा” व्यय में संबंधित लेखा जीर्य में या उसमें।

17ब. बैंक खाते: (1) बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी समनुरंगी बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाएंगे और उनका संचालन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसी महानिर्देशक प्राधिकृत करे।

(2) निधि में संबंधित सभी राशियां बैंक में सुरक्षा जगा कराई जाएंगी।

17च. विनिधान:—निधि में रावंधित राशियों का, महानिर्देशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुमोदन से, विनिधान पूर्ण रूप में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए व्याप के अधीन धारित सम्पत्ति में प्राप्त आय के विनिधान के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 113) की धारा 11 की उपयाग (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रूप और हंग में किया जाएगा।

17च. संविदा:—(1) व्युग्र अधिनियम के किसी भी उपबंध को कार्यान्वयन करने के लिए कोई भी ऐसी संविदा कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(2) अधिनियम के अधीन या उसके किसी प्रयोजन के लिए की गई प्रत्येक गत्रिका व्यूगों की ओर ने महानिर्देशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी।

17छ. भवित्व निधि का प्रबंध:—(1) व्युगों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू अभिदारी भवित्व निधि और साधारण भवित्व निधि का प्रबंध प्रशासनों की एक ऐसी

समिति द्वारा किया जाएगा जिसे महानिर्देशक निर्दिष्ट करे और यह समिति एक अध्यक्ष और चार अन्य अधिकारीयों में, जिनमें कम से कम दो अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे, मिलकर बनेगी।

(2) प्रशासनों की समिति के कुल्यों में भवित्व निधि का प्रबंध और उनका सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य विक्षेपों में, इस मंबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकारित रीति से विनिधान, सम्मिलित होगा। उसे ऐसे कुल्यों को जो वह आवश्यक समझे अपने एक या एक से अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करने की भी शक्ति होगी।

[स. 6(1)/88-बी. आई. एम.]
ग्रम. क्र. जुत्ती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना मा. का. नि. 361 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987 द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात् उसका संशोधन अधिसूचना मा. का. नि. 7(अ) तारीख 6 जनवरी, 1989 और अधिसूचना मा. का. नि. 48(अ), तारीख 2 फरवरी, 1990 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1990

G.S.R. 543(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards Second (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, after rule 17, the following rule, shall be inserted, namely:—

“17A. Expenditure not Budgeted for.—The expenditure which is of an emergent and essential in character but provision for the same has not been made in the budget shall be incurred only after the Executive Committee has approved of it.

17B. Appropriation.—The fund, provided in the sanctioned budget shall be deemed to be a the disposal of the Director-General who shall have full powers to appropriate sum therefrom to meet expenditure under different heads of accounts for activities an purposes authorised and provided for in the budget:

Provided that funds shall not be appropriated or reappropriated to meet expenditure which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it.

17C. Reappropriation.—The Director-General shall have powers within the scope of the budgeted activities and purposes to reappropriate sums from one head of account to another:

Provided that funds shall not be reappropriated—

- (i) to meet the expenditure on any new item of work not contemplated in the budget;
- (ii) to meet the expenditure on any Project involving construction which has not received administrative approval and technical sanction from the competent authorities;
- (iii) to meet the expenditure on any Project involving construction, in excess of 10 per cent of the approved estimates;
- (iv) from the provision made for any specified new item of expenditure in the budget for any other purpose;
- (v) from funds provided under Plan heads to the Non-Plan heads of expenditure and from Capital to Revenue and vice versa; and
- (vi) from or to head of account "Overseas travel" expenditure.

17D. Bank Accounts.—(1) Bank accounts shall be opened in State Bank of India or any of its subsidiaries or any of the nationalized banks and operated in such a manner as may be authorised by the Director-General.

(2) All moneys belonging to the Fund shall be deposited promptly into the Bank.

17E. Investment.—Money, belonging to the Fund may, with the approval of the Director-General or any other Officer authorized in

this behalf, be invested in the form and modes as specified under sub-section (5) of section 11 of the Income-tax Act, 1961 (113 of 1961) for investment of Income derived from Property held under trust wholly for Charitable or religious purposes.

17F. Contract.—(1) The Bureau may enter into all such contracts as it may consider necessary for giving effect to any of the provisions of the Act.

(2) Every contract made under or for any purpose of the Act shall be made on behalf of the Bureau by the Director-General or such other officers as may be authorised by him in this behalf.

17G. Administration of Provident Fund.—(1) Contributory Provident Fund and General Provident Fund applicable to the officers and employees of the Bureau shall be administered by a committee of administrators, to be nominated by the Director-General, comprising a Chairman and four other persons out of which at least two of them shall be the representatives of officers and employees.

(2) The functions of the committee of administrators shall include management of the Provident Funds and investment of the same in Government Securities and other deposits, in the manner laid down by the Central Government in this regard. It shall also have the power to delegate such of the functions as it may consider necessary to one or more of its members."

[No. 6(1)88-BIS]
M. K. ZUTSHI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was notified vide No. G.S.R. 361(E) dated 1st April, 1987, and subsequently amended vide notification No. G.S.R. 7(E) dated 6th January, 1939, and notification No. G.S.R. 48(E) dated 2nd February, 1990.

